

[2014] 7 एस सी आर 336

राजस्थान आर एस एस एंड जिनिंग मिल्स फेड लिमिटेड

बनाम

उप आयकर आयुक्त, जयपुर

(2003 की सिविल अपील संख्या 3880)

अप्रैल 29, 2014

[अनिल आर दवे और शिवा कीर्ति सिंह, जेजे]

आयकर अधिनियम 1961 - 85.72 और 72ए - सहकारी समिति - समामेलन - समामेलित समाज के मुनाफे के विरुद्ध समामेलित समितियों के नुकसान की भरपाई - पात्रता - चार सहकारी समितियां जिनमें राज्य सरकार की पर्याप्त हिस्सेदारी थी, समामेलित अपीलकर्ता सहकारी समिति की जानकारी - समामेलन पर, उक्त चार सहकारी समितियों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया और उनकी सभी संपत्तियों और देनदारियों को अपीलकर्ता समिति ने अपने कब्जे में ले लिया - समामेलन के बाद, जब अपीलकर्ता समिति द्वारा आयकर रिटर्न दाखिल किया गया, तो वह जमा होना चाहती थी उपरोक्त चार सोसाइटियों के घाटे को आगे बढ़ाया गया, ताकि इसे अपीलकर्ता सोसाइटी के मुनाफे के विरुद्ध समायोजित किया जा सके - अपीलकर्ता-सोसायटी का दावा - यदि तर्कसंगत हो - माना गया: जहां तक कंपनियों का संबंध है, आय में विशिष्ट प्रावधान है कर अधिनियम में कहा गया है कि एक कंपनी को दूसरी कंपनी के साथ मिलाने पर, समामेलित कंपनियों के घाटे को आगे बढ़ाया जा सकता है और एकीकृत कंपनी उन घाटे को अधिनियम के प्रावधानों के अधीन अपने मुनाफे के विरुद्ध समायोजित कर सकती है - लेकिन जैसा कि प्रासंगिक समय में ऐसा नहीं था समामेलित सोसाइटियों के संचित घाटे को समामेलित सोसाइटियों के मुनाफे से समायोजित करने के लिए अधिनियम के तहत प्रावधान, अपीलकर्ता सोसाइटी को पूर्ववर्ती सोसाइटियों के नुकसान को आगे बढ़ाने का लाभ नहीं मिल सकता था जो प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष के दौरान अस्तित्व में नहीं थे - सोसाइटियां और कंपनियां अलग-अलग वर्गों से संबंधित हैं और केवल इसलिए कि दोनों का एक अलग कानूनी व्यक्तित्व है, यह नहीं कहा जा सकता है कि दोनों को एक ही उपचार दिया जाना चाहिए - कराधान कानूनों की सख्ती से व्याख्या की जानी चाहिए = कराधान के मामलों में कोई समानता नहीं - राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1965 - धारा 16(8)।

कानूनों की व्याख्या - कर कानून - सख्त व्याख्या की आवश्यकता - कराधान के मामलों में कोई समानता नहीं।

राजस्थान सरकार द्वारा लिए गए एक प्रशासनिक निर्णय के तहत, चार सहकारी समितियों, जिनमें राजस्थान सरकार की पर्याप्त हिस्सेदारी थी, को 01/01/1993 से अपीलकर्ता सहकारी समिति में मिला दिया गया था। समामेलन पर, उक्त चार सहकारी समितियों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया और उक्त चार समितियों की सभी संपत्तियाँ और देनदारियों को अपीलकर्ता समिति ने अपने कब्जे में ले लिया। उपरोक्त चार समितियाँ आर्थिक रूप से मजबूत नहीं थीं और उन्हें काफी घाटा हुआ था। समामेलन के बाद, जब अपीलकर्ता सोसायटी द्वारा निर्धारण वर्ष 1994-95 और 1995-86 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल किया गया, तो वह पूर्वोक्त चार सोसायटी के संचित घाटे को आगे बढ़ाना चाहती थी, ताकि उसे समायोजित किया जा सके। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 72 के प्रावधानों के तहत अपीलकर्ता समाज का मुनाफा।

अपीलकर्ता के दावे को निर्धारण अधिकारी ने इस आधार पर खारिज कर दिया था कि अपीलकर्ता सोसायटी में एकीकरण के बाद उक्त समितियाँ अस्तित्व में नहीं थीं; और चूंकि उक्त चार सोसायटी अस्तित्व में नहीं थीं, इसलिए उनके संचित घाटे को अपीलकर्ता सोसायटी के मुनाफे के विरुद्ध आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था या समायोजित नहीं किया जा सकता था। मूल्यांकन आदेश को सीआईटी (अपील), आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था।

तत्काल अपील में, अपीलकर्ता समाज की ओर से मुख्य दलील यह थी कि अपीलकर्ता समाज को, एक समामेलित समाज होने के नाते, उन सहकारी समितियों के घाटे की भरपाई का लाभ मिलना चाहिए, जिन्हें अपीलकर्ता समाज में समामेलित किया गया था। यह तर्क दिया गया कि राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1965 की धारा 16(8) के प्रावधानों के आधार पर, अधिनियम की धारा 72 और 72(ए) के साथ पठित, समामेलित समितियों के संचित घाटे की अनुमति दी जानी चाहिए थी अपीलकर्ता समाज के मुनाफे के विरुद्ध समायोजित या समायोजित किया जाना; और यह कि राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1965 की धारा 16(8) के आधार पर विलय करने वाली सहकारी समितियों के खिलाफ या उनके द्वारा शुरू की गई सभी कानूनी कार्यवाही जारी रहेगी और इसलिए, अपने

घाटे की भरपाई के संबंध में विलय करने वाली समितियों का अधिकार है एकीकृत समाज के मुनाफों के खिलाफ आगे बढ़ना और बंद करना जारी रहेगा।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए

माना:1.1 घाटे को आगे बढ़ाने या बाद के वर्षों के मुनाफे के मुकाबले समायोजित करने के उद्देश्य से, आयकर अधिनियम, 1961 में कुछ प्रावधान होना चाहिए। यदि कोई प्रावधान नहीं है, तो जो समितियां अस्तित्व में नहीं हैं, उन्हें लाभ नहीं मिल सकता है। कोई लाभ. नुकसान उन समाजों को उठाना पड़ा जो प्रासंगिक समय में अस्तित्व में थे और उनका अस्तित्व या कानूनी व्यक्तित्व दूसरे समाज में समाहित होने पर समाप्त हो गया था। [पैरा 16]

1.2 सामान्य सिद्धांत यह है कि कोई अस्तित्वहीन व्यक्ति आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर सकता है और इसलिए, उसका अस्तित्व समाप्त होने के बाद वह अपने नुकसान को आगे नहीं बढ़ा सकता है। अपीलकर्ता सोसायटी में शामिल होने पर उन सभी चार सोसाइटियों का अस्तित्व समाप्त हो गया था और उन सोसाइटियों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया था। इन परिस्थितियों में, उन समाजों को अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपने पहले के नुकसान को एक अलग कानूनी व्यक्तित्व यानी अपीलकर्ता समाज की आय के खिलाफ समायोजित करने के लिए रिटर्न दाखिल करने का कोई अधिकार नहीं था। [पैरा 17]

1.3 जहां तक कंपनियों का सवाल है, आयकर अधिनियम में एक विशिष्ट प्रावधान है कि एक कंपनी को दूसरी कंपनी के साथ मिलाने पर, समामेलित कंपनियों के घाटे को आगे बढ़ाया जा सकता है और समामेलित कंपनी उन घाटे को अपने लाभ के विरुद्ध समायोजित कर सकती है। अधिनियम के प्रावधानों के लिए. आयकर अधिनियम की धारा 72 ए के आधार पर इसकी अनुमति है लेकिन सहकारी समितियों के मामले में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यह ध्यान देने योग्य है कि ऐसा प्रावधान केवल कंपनियों के समामेलन के संबंध में किया गया है और बाद में बैंकों आदि के संबंध में भी इसी तरह के प्रावधान किए गए, लेकिन प्रासंगिक समय में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जो समामेलन की अनुमति दे सके। ऑपरेटिव सोसाइटी को ऐसे घाटे को आगे बढ़ाने और समामेलित सहकारी सोसाइटी के मुनाफे के विरुद्ध समायोजित करने का अधिकार है। [पैरा 18,19]

1.4 भेदभाव और संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के संबंध में अपीलकर्ता की ओर से की गई दलील को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें कोई भेदभाव नहीं है।

सोसायटी और कंपनियां अलग-अलग वर्गों से संबंधित हैं और केवल इसलिए कि दोनों का एक अलग कानूनी व्यक्तित्व है, यह नहीं कहा जा सकता है कि दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। [पैरा 20]

1.5 चूँकि अधिनियम के तहत समामेलित सोसाइटियों के संचित घाटे को समामेलित सोसाइटियों के मुनाफों से समायोजित करने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए अपीलकर्ता सोसाइटी को उन पूर्ववर्ती सोसाइटियों के नुकसान को आगे बढ़ाने का लाभ नहीं मिल सकता था जो अस्तित्व में नहीं थीं। प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष. [पैरा 21]

1.6 साथ ही, सभी कर मामलों में कराधान क़ानून की कड़ाई से व्याख्या करनी होगी। सिर्फ इसलिए कि कानूनी संस्थाओं के एक वर्ग को कुछ लाभ दिया जाता है जो विशेष रूप से अधिनियम में बताया गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि कानूनी संस्थाओं को नहीं अधिनियम में उल्लिखित को भी वही लाभ मिलेगा। कराधान के मामलों में कोई समानता नहीं है। कोई भी उस अनुभाग को नहीं पढ़ सकता है जिसके लिए विशेष रूप से प्रावधान नहीं किया गया है और इसलिए, कोई उस अनुभाग में कुछ भी नहीं पढ़ सकता है जिसके लिए प्रदान नहीं किया गया है। [पैरा 22]

“आयकर आयुक्त, लखनऊ बनाम श्री माधो पीडी जटिया 1976(4) एससीसी 92: 1977 (1) एससीआर 665; मेसर्स बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन (प्राइवेट) लिमिटेड, झाँसी बनाम उत्पाद शुल्क आयुक्त, यूपी और अन्य 1971(1) एससीसी 4: 19871 (2) एससीआर 590; और आयकर आयुक्त, बॉम्बे बनाम महाराष्ट्र शुगर मिल्स लिमिटेड, बॉम्बे 1971 (3) एससीसी 543: 1972 (1) एससीआर 202 - पर निर्भर।

आय आयुक्त: टैक्स बनाम मेसर्स शाह सादिक एंड संस 1987(3) एससीसी 516: 1987 (2) एससीआर 942 - संदर्भित।

केस कानून संदर्भ:

1987 (2) एससीआर 942	पैरा 8	संदर्भित करता है
1977 (1) एससीआर 665	पैरा 12	पर निर्भर था
1971 (2) एससीआर 590	पैरा 12	पर निर्भर था

सिविल अपील की क्षेत्राधिकार: 2003 की सिविल अपील संख्या 3880।

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर शाखा, जयपुर के दिनांक 19/09/2002 के निर्णय और आदेश से, 2001 की डीबी आय, कर अपील संख्या 19 में।

अपीलार्थी की ओर से पुनीत जैन (प्रतिभा जैन के लिए)।

प्रतिवादी की ओर से एच राघवेंद्र राव (अनिल कटियार के लिए)।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

अनिल आर दवे, जे 1. राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ द्वारा 2001 की आयकर अपील संख्या 19 में 19 सितंबर, 2002 को दिए गए फैसले से व्यथित होकर, यह अपील निर्धारित द्वारा दायर की गई है, जो एक सह है -ऑपरेटिव सोसायटी. जब अपील को सुनवाई के लिए बुलाया गया, तो अपीलकर्ता सहकारी समिति की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर हमने पाया कि जो विद्वान वकील पहले पेश हुआ था वह वरिष्ठ वकील बन गया है। इन परिस्थितियों में, हमने उनके सहयोगी से इस मामले में उपस्थित होने का अनुरोध किया था, लेकिन उन्होंने अपीलकर्ता समाज की ओर से उपस्थित होने में अपनी अनिच्छा दिखाई थी, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यद्यपि वकालतनामा भेजने के लिए अपीलकर्ता समाज को दो से अधिक पत्र भेजे गए थे। इस न्यायालय में अपनी उपस्थिति के लिए उचित व्यवस्था करने के लिए, अपीलकर्ता समाज ने उक्त पत्रों का उत्तर देने की भी परवाह नहीं की। चूंकि अपीलकर्ता समाज एक ऐसा समाज है जिसमें राजस्थान राज्य का पर्याप्त हित है, हमने विद्वान अधिवक्ता श्री पुनीत जैन से अपीलकर्ता समाज की ओर से उपस्थित होकर अदालत की सहायता करने का अनुरोध किया था और इस न्यायालय के अनुरोध के अनुसरण में, उन्होंने अपनी बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी। अपीलकर्ता समाज की ओर से उपस्थित होकर।

2. वर्तमान अपील को जन्म देने वाले तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं:

राजस्थान राज्य में चार सहकारी समितियाँ थीं जिनमें राजस्थान सरकार की पर्याप्त हिस्सेदारी थी, अर्थात् - (i) राजस्थान सहकारी स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड; (ii) गंगापुर सहकारी स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड; (iii) गंगानगर सहकारी स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड; और (iv)

गुड़आबपुरा कॉटन जिनिंग एंड प्रेसिंग सहकारी समिति लिमिटेड, राजस्थान सरकार द्वारा सभी वनीकृत सहकारी समितियों को अपीलकर्ता सहकारी समिति, अर्थात् राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग और जिनिंग मिल्स फेडरेशन लिमिटेड में मिलाने का एक प्रशासनिक निर्णय लिया गया था। 01/01/1993.

उक्त समितियों के अपीलकर्ता समिति में सम्मेलन पर, उक्त चार सहकारी समितियों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया था और उक्त चार समितियों की सभी संपत्तियों और देनदारियों को उपरोक्त सम्मेलन के आधार पर अपीलकर्ता समिति ने अपने कब्जे में ले लिया था। उपरोक्त चार समितियां आर्थिक रूप से मजबूत नहीं थीं और उन्हें काफी घाटा हुआ था। अपीलकर्ता सोसायटी में चार सहकारी समितियों के सम्मेलन के बाद, जब मूल्यांकन वर्ष 1994-95 और 1995-96 के लिए आयकर रिटर्न अपीलकर्ता सोसायटी द्वारा दाखिल किए गए, तो अपीलकर्ता सोसायटी पूर्वोक्त के संचित घाटे को प्राप्त करना चाहती थी। लगभग 2,68,39,504/- रुपये की राशि को सोसायटी ने आगे बढ़ाया, ताकि इसे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 72 के प्रावधानों के तहत अपीलकर्ता सोसायटी के मुनाफे के विरुद्ध समायोजित किया जा सके (इसके बाद इसे कहा जाएगा)। कार्य)।

मूल्यांकन अधिकारी ने अपीलकर्ता के दावे को इस कारण से खारिज कर दिया कि अपीलकर्ता सोसायटी में विलय के बाद उक्त समितियां अस्तित्व में नहीं थीं। चूंकि उक्त चार समितियाँ अस्तित्व में नहीं थीं, मूल्यांकन अधिकारी के अनुसार, उनके संचित घाटे को अपीलकर्ता सोसायटी के मुनाफे के विरुद्ध आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था या समायोजित नहीं किया जा सकता था। तदनुसार मूल्यांकन आदेश पारित किए गए।

3 उपर्युक्त मूल्यांकन आदेशों से व्यथित होकर, सीआईटी (अपील) के समक्ष अपील दायर की गई और सीआईटी (अपील) ने उक्त अपील को खारिज कर दिया। आगे की अपीलें आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष दायर की गईं लेकिन न्यायाधिकरण ने भी अपीलों को खारिज कर दिया।

4 ट्रिब्यूनल द्वारा पारित सामान्य आदेश से व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष 2001 की आयकर अपील संख्या 19 दायर की और उक्त आयकर अपील भी खारिज कर दी गई और इसलिए, अपीलकर्ता ने वर्तमान के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। निवेदन।

5 अपीलकर्ता सोसायटी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया था कि मूल्यांकन अधिकारी और नीचे के प्राधिकारी, मूल्यांकन अधिकारी द्वारा लिए गए दृष्टिकोण की पुष्टि करते हुए, इस कारण से सही नहीं हैं कि अपीलकर्ता सोसायटी में उपरोक्त चार सहकारी समितियों के सम्मेलन पर राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 16(8) के प्रावधानों के आधार पर, इस प्रकार सम्मेलित समितियों के अधिकार और दायित्व प्रभावित नहीं होंगे और इसलिए, अपने कार्यों को आगे बढ़ाने के संबंध में समितियों के पास मौजूद सभी अधिकार घाटा जारी रहेगा, और चूंकि उक्त सोसाइटियों को अपीलकर्ता सोसायटी में मिला दिया गया है, अपीलकर्ता सोसायटी को सम्मेलित सोसायटियों को हुए नुकसान की भरपाई करने की अनुमति दी जानी चाहिए। विद्वान वकील ने राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1965 की धारा 16(8) पर भरोसा किया था, जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"16(8) इस धारा के तहत किया गया एकीकरण, स्थानांतरण या विभाजन इस प्रकार सम्मेलित समाजों के, या इस प्रकार विभाजित समाज के या हस्तांतरित व्यक्ति के किसी भी अधिकार या दायित्व को प्रभावित नहीं करेगा, या किसी भी कानूनी कार्यवाही को दोषपूर्ण बना देगा जो हो सकता है- उन सोसाइटियों द्वारा या उनके विरुद्ध जारी या शुरू किया गया जो सम्मेलित या विभाजित हो गई हैं या हस्तांतरित हो गईं; और तदनुसार ऐसी कानूनी कार्यवाही सम्मेलित सोसायटी, नई सोसायटी या हस्तांतरित व्यक्ति द्वारा या उसके विरुद्ध, जैसा भी मामला हो, जारी या शुरू की जा सकती है।"

6 विद्वान वकील ने आगे कहा था कि अधिनियम की धारा 72(1) को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1965 की धारा 16(8) के साथ पढ़ने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अपीलकर्ता निर्धारिता को विलय से होने वाले नुकसान को आगे बढ़ाने का अधिकार था। सोसायटी और उक्त सोसायटी के व्यापारिक घाटे को अपीलकर्ता सोसायटी के लाभ और लाभ के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।

7. उन्होंने आगे कहा था कि अधिनियम की धारा 72 (ए) में प्रयुक्त 'कंपनी' शब्द की व्यापक व्याख्या की जानी चाहिए ताकि 'कंपनी' शब्द में समाजों को शामिल किया जा सके क्योंकि कंपनियों की तरह, समाजों का भी एक अलग कानूनी व्यक्तित्व होता है और अधिनियम के तहत अधिकारियों के पास सहकारी समितियों के साथ अलग व्यवहार करने का कोई कारण नहीं है।

8 आगे यह प्रस्तुत किया गया था कि अपीलकर्ता सोसायटी के पास एकीकृत सोसायटी के संचित घाटे को अपीलार्थी सोसायटी के मुनाफे के विरुद्ध समायोजित करने का निहित अधिकार था और उक्त निहित अधिकार को मूल्यांकन अधिकारी द्वारा छीना नहीं जा सकता था। अपनी दलील को पुष्ट करने के लिए, उन्होंने आयकर आयुक्त बनाम मेसर शाह सादिक एंड संस 1987(3) एससीसी 516 के मामले में दिए गए फैसले पर भरोसा किया था।

9 इसलिए, उन्होंने प्रस्तुत किया था कि अपील की अनुमति दी जानी चाहिए और अपीलकर्ता समाज को अपीलकर्ता समाज के मुनाफे के खिलाफ समामेलित समाजों के संचित घाटे को समायोजित करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

10 दूसरी ओर, आयकर विभाग के अधिकारियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया था कि तथ्य के समवर्ती निष्कर्ष, और नीचे के सभी अधिकारियों और उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विचार बिल्कुल सही थे और इसलिए, आक्षेपित निर्णय किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी। उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि समामेलन सोसायटियों का पंजीकरण समामेलन पर रद्द कर दिया गया था और चूंकि वे उस समय अस्तित्व में नहीं थे जब अपीलकर्ता समाज का मूल्यांकन किया गया था, समामेलन सोसायटियों के संचित घाटे को आगे बढ़ाने का कोई सवाल ही नहीं था और उन्हें अपीलकर्ता समाज के मुनाफे के विरुद्ध समायोजित करना।

11 उन्होंने हमारा ध्यान अधिनियम की धारा 72 और 72ए के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया था। उन्होंने आगे कहा था कि अधिनियम की धारा 72 और 72ए को संयुक्त रूप से पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि यदि उक्त समितियां अस्तित्व में नहीं थीं, तो सहकारी समितियों को आगे बढ़ने और संचित घाटे की भरपाई करने का लाभ नहीं मिल सकता है। केवल एक 'कंपनी' के मामले में, एक समामेलित कंपनी द्वारा सेट-ऑफ का लाभ उठाया जा सकता है, यदि समामेलित कंपनी को घाटा हुआ हो, जिसे आगे बढ़ाया जा सकता था और प्रावधानों के अनुसार समामेलित कंपनी के मुनाफे के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता था। अधिनियम।

12 अपनी दलीलों को प्रमाणित करने के लिए, उन्होंने आयकर आयुक्त, लखनऊ बनाम श्री माधो पीडी जटिया 1976(4) एससीसी 92 और मेसर बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन (प्राइवेट) लिमिटेड, झाँसी बनाम उत्पाद शुल्क के मामले में दिए गए निर्णयों पर भरोसा किया था। आयुक्त, उत्तर प्रदेश और अन्य 1971(1) एससीसी 4 उन्होंने आयकर आयुक्त, बॉम्बे बनाम

महाराष्ट्र शुगर मिल्स-लिमिटेड, बॉम्बे 1971 (3) एससीसी 543 के मामले में दिए गए फैसले पर भी भरोसा किया था। उपरोक्त निर्णयों के अवलोकन पर ; जो आयकर अधिकारियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील का समर्थन करते हैं, यह स्पष्ट है कि कर कानून की व्याख्या बहुत सख्ती से की जानी चाहिए क्योंकि कर मामलों में कोई समानता नहीं है और कुछ भी नहीं पढ़ा जा सकता है जो अनुभाग में नहीं है।

13 इस प्रकार, प्रतिवादी अधिकारियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया था कि आक्षेपित निर्णय उचित और सही है और इसलिए, अपील खारिज करने योग्य है।

14 हमने विद्वान वकील को सुना था और मामले से संबंधित अभिलेखों का भी अवलोकन किया था और उनके द्वारा संदर्भित निर्णयों को भी देखा था, और उन्हें सुनने के बाद हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय बिल्कुल न्यायपूर्ण और उचित है। .

15 अपीलकर्ता समाज की ओर से उपस्थित विद्वान वकील का मुख्य तर्क यह था कि अपीलकर्ता समाज, एक समामेलित समाज होने के नाते, उन सहकारी समितियों के घाटे की भरपाई का लाभ प्राप्त करना चाहिए जिन्हें अपीलकर्ता समाज में समामेलित किया गया था। उनके अनुसार राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1965 की धारा 16(8) के प्रावधानों के आधार पर, अधिनियम की धारा 72 और 72(ए) के साथ पठित, समामेलित समितियों के संचित घाटे की अनुमति दी जानी चाहिए थी अपीलकर्ता सोसायटी के मुनाफे के विरुद्ध समायोजित या सेट ऑफ किया जाएगा। उनका मुख्य तर्क यह था कि राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1965 की धारा 16(8) के आधार पर, विलय करने वाली सहकारी समितियों के खिलाफ या उनके द्वारा शुरू की गई सभी कानूनी कार्यवाही जारी रहेगी और इसलिए, प्राप्त करने के संबंध में विलय करने वाली समितियों का अधिकार उनके घाटे को आगे बढ़ाया गया और एकीकृत समाज के मुनाफों के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी।

16 हम अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा की गई दलीलों से सहमत नहीं हैं क्योंकि घाटे को अगले वर्षों के मुनाफे के विरुद्ध समायोजित या समायोजित करने के उद्देश्य से, अधिनियम में कुछ प्रावधान होना चाहिए। यदि कोई प्रावधान नहीं है, तो जो समाज अस्तित्व में नहीं हैं, उन्हें कोई लाभ नहीं मिल सकता है। नुकसान उन समाजों को उठाना पड़ा जो प्रासंगिक समय में अस्तित्व में थे और उनका अस्तित्व या कानूनी व्यक्तित्व दूसरे समाज में समाहित होने पर समाप्त हो गया था।

17 सामान्य सिद्धांत: यह है कि एक गैर-मौजूद व्यक्ति आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर सकता है और इसलिए, इसका अस्तित्व समाप्त होने के बाद इसके नुकसान को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। अपीलकर्ता सोसायटी में शामिल होने पर उन सभी चार सोसाइटियों का अस्तित्व समाप्त हो गया था और उन सोसाइटियों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया था। इन परिस्थितियों में, उन समाजों को अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपने पिछले नुकसान को एक अलग कानूनी व्यक्तित्व यानी अपीलकर्ता समाज की आय के विरुद्ध समायोजित करने के लिए रिटर्न दाखिल करने का कोई अधिकार नहीं था।

18 जहां तक कंपनियों का सवाल है, अधिनियम में एक विशिष्ट प्रावधान है कि एक कंपनी को दूसरी कंपनी के साथ मिलाने पर, समामेलित कंपनियों के घाटे को आगे बढ़ाया जा सकता है और समामेलित कंपनी उन घाटे को अपने मुनाफे से समायोजित कर सकती है, बशर्ते कि अधिनियम के प्रावधान. अधिनियम की धारा 72 ए के आधार पर इसकी अनुमति है लेकिन सहकारी समितियों के मामले में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

19 यह ध्यान देने योग्य है कि ऐसा प्रावधान केवल कंपनियों के समामेलन के संबंध में किया गया है और बाद में बैंकों आदि के संबंध में भी इसी तरह के प्रावधान किए गए, लेकिन प्रासंगिक समय में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जो समामेलन की अनुमति देता। - ऑपरेटिव सोसायटी को एकीकृत सहकारी सोसायटी के मुनाफे के खिलाफ ऐसे घाटे को आगे बढ़ाना और समायोजित करना होगा।

20 भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के भेदभाव और उल्लंघन के संबंध में अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा की गई दलील से भी अपीलकर्ता को मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारी राय में, कोई भेदभाव नहीं है। सोसायटी और कंपनियां अलग-अलग वर्गों से संबंधित हैं और केवल इसलिए कि दोनों का एक अलग कानूनी व्यक्तित्व है, यह नहीं कहा जा सकता है कि दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए।

21 हम उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विचार से सहमत हैं कि चूंकि अधिनियम के तहत समामेलित समाजों के संचित घाटे को एकीकृत समाज के मुनाफे के विरुद्ध समायोजित करने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए अपीलकर्ता समाज को घाटे को आगे बढ़ाने का लाभ नहीं मिल सकता था। पूर्ववर्ती समाजों का जो प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष के दौरान अस्तित्व में नहीं थे।

22 हमारा यह भी विचार है कि सभी कर मामलों में कराधान कानून की कड़ाई से व्याख्या करनी होगी। सिर्फ इसलिए कि कानूनी संस्थाओं के एक वर्ग को कुछ लाभ दिया जाता है जो विशेष रूप से अधिनियम में बताया गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि अधिनियम में संदर्भित नहीं की गई कानूनी संस्थाओं को भी वही लाभ मिलेगा। जैसा कि इस न्यायालय ने कई अवसरों पर कहा है, कराधान के मामलों में कोई समानता नहीं है। कोई भी ऐसे अनुभाग को नहीं पढ़ सकता है जिसके लिए विशेष रूप से प्रावधान नहीं किया गया है और इसलिए, हम अपीलकर्ता के लिए उपस्थित विद्वान वकील की दलीलों से सहमत नहीं हैं और हम उस अनुभाग में कुछ भी पढ़ने के लिए तैयार नहीं हैं जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है। यहां ऊपर उल्लिखित निर्णय उस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं जो हमने यहां व्यक्त किया है।

23 यहां ऊपर बताए गए कारणों से, लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के अपील खारिज कर दी जाती है।

विभूति भूषण बोस

अपील खारिज।